



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 18, 2013/चैत्र 28, 1935

No. 193]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 18, 2013/CHAITRA 28, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं. 6/2013-सेवा कर

सा.का.नि. 254(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, कराधेय क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्ट्रिप के एवज में प्रदान की गई या प्रदान किये जाने के लिए सहमति दी गई कर योग्य सेवा को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 66 ख के अंतर्गत लगाये जा सकने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है।

2. प्रवर्तन- यह अधिसूचना फोकस मार्केट स्कीम इयूटी क्रेडिट स्ट्रिप पर लागू होगी जो कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.14 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्यातक को जारी की गई हो।

3. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा :-

(क) यह कि इस स्ट्रिप को उन देशों को किये जाने वाले निर्यात के एवज में जारी किया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1 के परिशिष्ट 37क में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए हैं।

बशर्ते कि निम्नलिखित वर्ग के निर्यात (विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.17.2 और 3.14.3 में विनिर्दिष्ट) को फोकस मार्केट स्कीम के अंतर्गत निर्यात निष्पदन की गणना में या अधिकार की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यथा :-

- (i) निर्यातान्मुखी इकाइयां या इलेक्ट्रॉनिक हॉर्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क जिनको कि प्रत्यक्ष कर का लाभ मिल रहा है;
- (ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अंतर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात;
- (iii) ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से होने वाला निर्यात, जिसका अर्थ यह है कि निर्यात का प्रारम्भ तो तीसरे देश से हुआ हो लेकिन इसकी ट्रांसशिपिंग भारत से होते हुए की जा रही हो;
- (iv) मानक निर्यात;
- (v) विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा किए जाने वाला निर्यात, या विशेष आर्थिक जोन उत्पाद जिनका निर्यात घरेलू टैरिफ क्षेत्रों के माध्यम से किया गया हो;
- (vi) ऐसे मद जो कि आईटीसी (एचएस) कि निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात के लिए प्रतिसिद्ध या निषिद्ध हैं;
- (vii) विशेष आर्थिक जोन की इकाइयों को की गई आपूर्ति;
- (viii) सेवा निर्यात;
- (ix) हीरा एवं अन्य बहुमूल्य, अर्ध कीमती रत्न;
- (x) सोना, चांदी, प्लेटिनम या अन्य कीमती धातुएं, जो किसी भी रूप में हों जिनमें सादे और जड़ाऊ आभूषण शामिल हैं;
- (xi) अयस्क और सांद्र, सभी प्रकार के और सभी रूपों में;
- (xii) अनाज, सभी प्रकार के;
- (xiii) चीनी, सभी प्रकार की और सभी रूपों में;
- (xiv) कच्चे या पेट्रोलियम के और कच्चे या पेट्रोलियम आधारित उत्पाद जो कि आईटीसी एचएस कोड 2709 से 2715 के अंतर्गत आते हैं;
- (xv) ऐसे दूध और दुग्ध उत्पाद का निर्यात जो आईटीसी एचएस कोड जो 0401 से 0406, 19011001, 19011010, 2105 एवं 3501 के अंतर्गत आते हैं।
- (ख) यह कि वह स्क्रीप पंजीयन बंदरगाह पर सीमा शुल्क प्राधिकारी में (तत्पश्चात् उपर्युक्त सीमा शुल्क का अधिकारी के रूप में संदर्भित) के पास पंजीकृत होगी;
- (ग) यह कि स्क्रीप धारक, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई हैं अथवा प्रदान किये जाने की सहमति की गई है, कर योग्य क्षेत्र में स्थित होगा;
- (घ) यह कि स्क्रीप धारक जो कि वह व्यक्ति हो सकता है, जिसे मूल रूप में स्क्रीप जारी की गई थी अथवा कोई हस्तांतरित धारक हो सकता है, वह उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को एक पत्र के साथ तथा इनवाईस अथवा चालान अथवा बिल, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (तत्पश्चात् उपर्युक्त प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 (क) के अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा संबंधित स्क्रीप को प्रस्तुत करते हुए उसके विवरण तथा ब्यौरे, प्रदान की गई अथवा प्रदान किये जाने वाली सहमति वाली कर योग्य सेवा का मूल्य तथा उस पर लगाने वाले सेवा कर को इंगित करेगा;
- (ड.) यह कि उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी अधिसूचना सं. 93/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, अधिसूचना सं. 30/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 के अंतर्गत पहले ही दिये गये

डेबिट को तथा इस छूट को मद्देनजर रखते हुए रखेगा, इस प्रकार दी गई छूट को अथवा स्क्रीप के रिवर्स पर लगने वाले सेवा कर को डेबिट करेगा तथा उससे संबंधित अपेक्षित विवरण का भी उल्लेख करेगा और अपने ही रिकार्ड को अद्यतन करेगा तथा उपर्युक्त अधिकारी को कार्यवाइयों के बारे में लिखित सलाह देगा;

(च) यह कि उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा स्क्रीप में लगने वाले सेवा कर का डेबिट करने की तारीख को सेवा कर के भुगतान की तारीख के रूप में माना जायेगा;

(छ) यह कि यदि लगने वाला सेवा कर कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के शर्तों के अनुसार निर्धारित किये गये कराधान बिंदु डेबिट किये जाने की तारीख से पहले हो अथवा कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 4 की शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई कर की दर इनवाइस, बिल अथवा चलान, जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित सेवा कर दर से यदि अधिक हो, तो स्क्रीप धारा ऐसा ब्याज अथवा ब्याज सहित ऐसा सेवा कर जो कम दिया गया है, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करेगा;

(ज) यह कि स्क्रीप धारा उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा डेबिट की गई स्क्रीप को संबंधित अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को इस वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत करेगा कि यदि स्क्रीप में सेवा कर डेबिट में कोई कमी रहती है तो, वह लागू ब्याज सहित ऐसा सेवा कर का भुगतान करेगा ;

(झ) यह कि संबंधित लिखित सलाह तथा वचनबद्धता के आधार पर, संबंधित अधिकारी स्क्रीप के रिवर्स पर लगने वाले सेवा कर के विवरण को सत्यापित तथा वैध करेगा, जोकि उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा डेबिट किये गये थे तथा ऐसा सेवा कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, भुगतान का रिकार्ड रखेगा।

(ञ) यह कि सेवा प्रदाता उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा डेबिट की गई तथा संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई और स्क्रीप धारक द्वारा अनुप्रमाणित की गई स्क्रीप की एक प्रतिलिपि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं के उपबंधों के समर्थन में अपने पास रखेगा; तथा

(ट) यह कि संबंधित स्क्रीप धारा, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई थी अथवा प्रदान किये जाने की सहमति दी गई थी को स्क्रीप में डेबिट की गई सेवा कर के समक्ष उपर्युक्त अधिनियम की धारा 66ख के अंतर्गत सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट अथवा प्रति अदायगी का लाभ प्राप्त करने की हकदारी होगी तथा उसे संबंधित अधिकारी द्वारा वैध किया जायेगा।

4. इस अधिसूचना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को दिए कोई भी राशि उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत अपनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली योग्य होगी।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2009-14 से है, जिसको कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 01 (आरई 2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

(ख) "प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-1" से अभिप्राय प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-1, 2009-14 से है, जिसको कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लोक सूचना सं. 01(आरई 2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

(ग) "कराधान के बिंदु" का अर्थ वही है जो कि कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 2 के उपवाक्य (ड.) के अंतर्गत इसके लिए दिया गया है।

(घ) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है, जो कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत इयूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करने के लिए सक्षम है।

(ड.) "स्क्रिप" से अभिप्राय ऐसे फोकस मार्केट स्कीम इयूटी क्रेडिट स्क्रिप से है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.14 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्यातकर्ता को जारी की गई हो।

[फा. सं. 354/55/2013-टीआरयू]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th April, 2013

#### No. 6/2013-Service Tax

**G.S.R. 254(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994)(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services provided or agreed to be provided against a scrip by a person located in the taxable territory from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act.

2. Application. – This notification shall be applicable to the Focus Market Scheme duty credit scrip issued to an exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.14 of the Foreign Trade Policy.

3. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) that the scrip is issued against exports to the countries notified by the Government of India in Appendix 37C of the Handbook of Procedures, Volume I:

*Provided* that the following categories of exports (specified in paragraph 3.17.2 and 3.14.3 of the Foreign Trade Policy) shall not be counted for calculation of export performance or for computation of entitlement under the Focus Market Scheme, namely:-

(i) the Export Oriented Units or Electronic Hardware Technology Parks or Biotechnology Parks which are availing direct tax benefits or exemption;

(ii) the export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy;

(iii) the exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transhipped through India;

(iv) the deemed exports;

- (v) the exports made by Special Economic Zone units or Special Economic Zone products exported through Domestic Tariff Area units;
  - (vi) the items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS);
  - (vii) supplies made to Special Economic Zone units;
  - (viii) the service exports;
  - (ix) diamonds and other precious, semi precious stones;
  - (x) Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain and studded jewellery;
  - (xi) Ores and Concentrates, of all types and in all forms;
  - (xii) Cereals, of all types;
  - (xiii) the Sugar, of all types and in all forms;
  - (xiv) Crude or Petroleum oil and Crude or Petroleum based products covered under ITC HS codes 2709 to 2715, of all types and in all forms; and
  - (xv) the export of milk and milk products covered under ITC HS Codes 0401 to 0406, 19011001, 19011010, 2105 and 3501;
- (b) that the scrip is registered with the Customs Authority at the port of registration (hereinafter referred to as the said Customs Authority);
- (c) that the holder of the scrip, to whom taxable services are provided or agreed to be provided shall be located in the taxable territory;
- (d) that the holder of the scrip who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents the scrip to the said Customs Authority along with a letter and an invoice or challan or bill, as the case may be, issued under rule 4A of the Service Tax Rules, 1994 by the service provider indicating details of his jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred to as the said Officer) and the description, value of the taxable service provided or agreed to be provided and service tax leviable thereon;
- (e) that the said Customs Authority, taking into account the debits already made under notification number 93/2009-Customs, dated the 11th September, 2009, notification No.30/2012-Central Excise, dated the 9th July, 2012 and this exemption, shall debit the service tax leviable, but for this exemption in or on the reverse of the scrip and also mention the necessary details thereon, updates its own records and sends written advice of these actions to the said Officer;

1597 61/13-2

(f) that the date of debit of service tax leviable, in the scrip, by the said Customs Authority shall be taken as the date of payment of service tax;

(g) that in case the service tax leviable as per the point of taxation determined in terms of the Point of Taxation Rules, 2011 is prior to date of debit or that the rate of tax determined in terms of rule 4 of the Point of Taxation of Rules, 2011, is in excess of the rate of service tax mentioned in the invoice, bill or challan, as the case may be, the holder of the scrip shall pay such interest or short-paid service tax along with interest, as the case may be;

(h) that the holder of the scrip presents the scrip debited by the said Customs Authority within thirty days to the said Officer, along with an undertaking addressed to the said Officer, that in case of any service tax short debited in the scrip, shall pay such service tax along with applicable interest;

(i) that based on the said written advice and undertaking, the said Officer shall verify and validate, on the reverse of the scrip, the details of the service tax leviable, which were debited by the said Customs Authority, and keep a record of payment of such service tax and interest, if any;

(j) that the service provider retains a copy of the scrip, debited by the said Customs Authority and verified by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip, in support of the provision of taxable services under this notification; and

(k) that the said holder of the scrip, to whom the taxable services were provided or agreed to be provided shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the service tax leviable under section 66B of the said Act, against the service tax debited in the scrip and validated by the said Officer.

4. Any amount due to the Central Government under this notification shall be recoverable under the provisions of the said Act and the rules made there under.

*Explanation* - For the purposes of this notification,-

(A) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2009-14, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, vide notification No.01 (RE 2012)/2009-2014, dated the 5<sup>th</sup> June, 2012, as amended from time to time.

(B) "Handbook of Procedures Volume 1" means the Handbook of Procedures Volume 1, 2009-14, published by the Government of India

in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* Public Notice No.01 (RE 2012)/2009-2014, dated the 5<sup>th</sup> June, 2012, as amended from time to time.

(C) "Point of taxation" shall have the same meaning assigned to it in clause (e) of rule 2 of the Point of Taxation Rules, 2011.

(D) "Regional Authority" means the authority competent to grant a duty credit scrip under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).

(E) "Scrip" means Focus Market Scheme duty credit scrip issued to an exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.14 of the Foreign Trade Policy;

[F. No. 354/55/2013-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं. 7/2013-सेवा कर

सा.का.नि. 255(अ).—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, कराधेय क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्क्रिप के एवज में प्रदान की गई या प्रदान किये जाने के लिए सहमति दी गई कर योग्य सेवा को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 66 ख के अंतर्गत लगाये जा सकने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है।

2. प्रवर्तन- यह अधिसूचना फोकस प्रोडक्ट स्कीम इयूटी क्रेडिट स्क्रिप पर लागू होगी जो कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.15 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्यातक को जारी की गई हो।

3. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा :-

(क) यह कि इस स्क्रिप को उन देशों को उन उत्पादों के किये जाने वाले निर्यात के एवज में जारी किया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1 के परिशिष्ट 37घ में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं।

बशर्त कि निम्नलिखित वर्ग के निर्यात (विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.17.2 में विनिर्दिष्ट) को फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत निर्यात निष्पदन की गणना में या अधिकार की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यथा :-

(i) निर्यातानुमुखी इकाईयां या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क जिनको कि प्रत्यक्ष कर का लाभ मिल रहा है;

- (ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अंतर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात;
- (iii) ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से होने वाला निर्यात, जिसका अर्थ यह है कि निर्यात का प्रारम्भ तो तीसरे देश से हुआ हो लेकिन इसकी ट्रांसशिपिंग भारत से होते हुए की जा रही हो;
- (iv) मानक निर्यात;
- (v) विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा किए जाने वाला निर्यात, या विशेष आर्थिक जोन उत्पाद जिनका निर्यात घरेलू टैरिफ क्षेत्रों के माध्यम से किया गया हो ;
- (vi) ऐसे मद जो कि आईटीसी (एचएस) कि निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात के लिए प्रतिसिद्ध या निषिद्ध हैं;

(ख) यह कि वह स्क्रीप पंजीयन बंदरगाह पर सीमा शुल्क प्राधिकारी में (तत्पश्चात उपर्युक्त सीमा शुल्क का अधिकारी के रूप में संदर्भित) के पास पंजीकृत होगी;

(ग) यह कि स्क्रीप धारक, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई हैं अथवा प्रदान किये जाने की सहमति की गई है, कर योग्य क्षेत्र में स्थित होगा;

(घ) यह कि स्क्रीप धारक जो कि वह व्यक्ति हो सकता है, जिसे मूल रूप में स्क्रीप जारी की गई थी अथवा कोई हस्तांतरित धारक हो सकता है, वह उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को एक पत्र के साथ तथा इनवाइस अथवा चालान अथवा बिल, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (तत्पश्चात उपर्युक्त प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 (क) के अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा संबंधित स्क्रीप को प्रस्तुत करते हुए उसके विवरण तथा ब्याज, प्रदान की गई अथवा प्रदान किये जाने वाली सहमति वाली कर योग्य सेवा का मूल्य तथा उस पर लगने वाले सेवा कर को इंगित करेगा;

(ङ.) यह कि उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी अधिसूचना सं. 92/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, अधिसूचना सं. 29/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 के अंतर्गत पहले ही दिये गये डेबिट को तथा इस छूट को मद्देनजर रखते हुए रखेगा, इस प्रकार दी गई छूट को अथवा स्क्रीप के रिवर्स पर लगने वाले सेवा कर का डेबिट करेगा तथा उससे संबंधित अपेक्षित विवरण का भी उल्लेख करेगा और अपने ही रिकार्ड को अद्यतन करेगा तथा उपर्युक्त अधिकारी को कार्यवाहियों के बारे में लिखित सलाह देगा;

(च) यह कि उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा स्क्रीप में लगने वाले सेवा कर डेबिट करने की तारीख को सेवा कर के भुगतान की तारीख के रूप में माना जायेगा;

(छ) यह कि यदि लगने वाला सेवा कर कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के शर्तों के अनुसार निर्धारित किये गये कराधान बिंदु डेबिट किये जाने की तारीख से पहले हो अथवा कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 4 की शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई कर की दर इनवाइस, बिल अथवा चालान, जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित सेवा कर दर से यदि अधिक हो, तो स्क्रीप धारा ऐसा ब्याज अथवा ब्याज सहित ऐसा सेवा कर जो कम दिया गया है, जैसा भी मामला हो, का भुगतान करेगा;

(ज) यह कि स्क्रीप धारा उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा डेबिट कि गई स्क्रीप को संबंधित अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को इस वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत करेगा कि यदि स्क्रीप में सेवा कर डेबिट में कोई कमी रहती है तो, वह लागू ब्याज सहित ऐसा सेवा कर का भुगतान करेगा ;

(झ) यह कि संबंधित लिखित सलाह तथा वचनबद्धता के आधार पर, संबंधित अधिकारी स्क्रीप के रिवर्स पर लगने वाले सेवा कर के विवरण को सत्यापित तथा वैध करेगा, जोकि उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा डेबिट किये गये थे तथा ऐसा सेवा कर तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान का रिकार्ड रखेगा।



(अ) यह कि सेवा प्रदाता उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा डेबिट की गई तथा संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई और स्क्रीप धारक द्वारा अनुप्रमाणित की गई स्क्रीप की एक प्रतिलिपि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं के उपबंधों के समर्थन में अपने पास रखेगा; तथा

(द) यह कि संबंधित स्क्रीप धारा, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई थी अथवा प्रदान किये जाने की सहमति दी गई थी को स्क्रीप में डेबिट की गई सेवा कर के समक्ष उपर्युक्त अधिनियम की धारा 66ख के अंतर्गत सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट अथवा प्रति अदायगी का लाभ प्राप्त करने की हकदारी होगी तथा उसे संबंधित अधिकारी द्वारा वैध किया जायेगा।

4. इस अधिसूचना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को दिए कोई भी राशि उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत अपनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली योग्य होगी।

**स्पष्टीकरण-** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2009-14 से है, जिसको कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 01 (आरई 2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

(ख) "प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-1" से अभिप्राय प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-1, 2009-14 से है, जिसको कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लोक सूचना सं. 01(आरई 2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

(ग) "कराधान के बिंदु" का अर्थ वही है जो कि कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 2 के उपवाक्य (ड.) के अंतर्गत इसके लिए दिया गया है।

(घ) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है, जो कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत इयूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करने के लिए सक्षम है।

(ड.) "स्क्रिप" से अभिप्राय ऐसे फोकस प्रोडक्ट स्कीम इयूटी क्रेडिट स्क्रिप से है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.15 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्यतकर्ता को जारी की गई हो।

[फा. सं. 354/55/2013-टीआरयू]

राज कुमार दिग्विजय, अवर सचिव

1597 GI/13-3

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2013

**No. 7/2013-Service Tax**

**G.S.R. 255(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994)(hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services provided or agreed to be provided against a scrip by a person located in the taxable territory from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act.

2. Application. – This notification shall be applicable to the Focus Product Scheme duty credit scrip issued to an exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.15 of the Foreign Trade Policy.

3. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) that the scrip is issued against exports of the products listed by the Government of India in Appendix 37D of the Handbook of Procedures, Volume I:

*Provided* that the following categories of exports (specified in paragraph 3.17.2 of the Foreign Trade Policy) shall not be counted for calculation of export performance or for computation of entitlement under the Focus Product Scheme, namely:-

(i) the Export Oriented Units or Electronic Hardware Technology Parks or Biotechnology Parks which are availing direct tax benefits or exemption;

(ii) the export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy;

(iii) the exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transhipped through India;

(iv) the deemed exports;

(v) the exports made by Special Economic Zone units or Special Economic Zone products exported through Domestic Tariff Area units;

(vi) the items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS);

- (b) that the scrip is registered with the Customs Authority at the port of registration (hereinafter referred to as the said Customs Authority);
- (c) that the holder of the scrip, to whom taxable services are provided or agreed to be provided shall be located in the taxable territory;
- (d) that the holder of the scrip who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents the scrip to the said Customs Authority along with a letter and an invoice or challan or bill, as the case may be, issued under rule 4A of the Service Tax Rules, 1994 by the service provider indicating details of his jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred to as the said Officer) and the description, value of the taxable service provided or agreed to be provided and service tax leviable thereon;
- (e) that the said Customs Authority, taking into account the debits already made under notification number 92/2009-Customs, dated the 11th September, 2009, notification No.29/2012-Central Excise, dated the 9<sup>th</sup> July, 2012 and this exemption, shall debit the service tax leviable, but for this exemption in or on the reverse of the scrip and also mention the necessary details thereon, updates its own records and sends written advice of these actions to the said Officer;
- (f) that the date of debit of service tax leviable, in the scrip, by the said Customs Authority shall be taken as the date of payment of service tax;
- (g) that in case the service tax leviable as per the point of taxation determined in terms of the Point of Taxation Rules, 2011 is prior to date of debit or that the rate of tax determined in terms of rule 4 of the Point of Taxation of Rules, 2011, is in excess of the rate of service tax mentioned in the invoice, bill or challan, as the case may be, the holder of the scrip shall pay such interest or short-paid service tax along with interest, as the case may be;
- (h) that the holder of the scrip presents the scrip debited by the said Customs Authority within thirty days to the said Officer, along with an undertaking addressed to the said Officer, that in case of any service tax short debited in the scrip, shall pay such service tax along with applicable interest;
- (i) that based on the said written advice and undertaking, the said Officer shall verify and validate, on the reverse of the scrip, the details of the service tax leviable, which were debited by the said Customs Authority, and keep a record of payment of such service tax and interest, if any;
- (j) that the service provider retains a copy of the scrip, debited by the said Customs Authority and verified by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip, in support of the provision of taxable services under this notification; and
- (k) that the said holder of the scrip, to whom the taxable services were provided or agreed to be provided shall be entitled to avail the

drawback or CENVAT credit of the service tax leviable under section 66B of the said Act, against the service tax debited in the scrip and validated by the said Officer.

4. Any amount due to the Central Government under this notification shall be recoverable under the provisions of the said Act and the rules made there under.

**Explanation—**For the purposes of this notification, -

(A) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2009-14, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, vide notification No.01 (RE 2012)/2009-2014, dated the 5<sup>th</sup> June, 2012, as amended from time to time.

(B) "Handbook of Procedures Volume 1" means the Handbook of Procedures Volume 1, 2009-14, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, vide Public Notice No.01 (RE 2012)/2009-2014, dated the 5<sup>th</sup> June, 2012, as amended from time to time.

(C) "Point of taxation" shall have the same meaning assigned to it in clause (e) of rule 2 of the Point of Taxation Rules, 2011.

(D) "Regional Authority" means the authority competent to grant a duty credit scrip under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).

(E) "Scrip" means Focus Product Scheme duty credit scrip issued to an exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.15 of the Foreign Trade Policy.

[F. No. 354/55/2013-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2013

सं. 8/2013-सेवा कर

**सा.का.नि. 256(अ).**—वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्वारा, कराधेय क्षेत्र में अवस्थित किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्क्रिप के एवज में प्रदान की गई या प्रदान किये जाने के लिए सहमति दी गई कर योग्य सेवा को उस पर उक्त अधिनियम की धारा 66 ख के अंतर्गत लगाये जा सकने वाले संपूर्ण सेवा कर से छूट प्रदान करती है।

2. प्रवर्तन- यह अधिसूचना विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (स्पेशल एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री स्कीम) इयूटी क्रेडिट स्क्रिप पर लागू होगी जो कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.13.2 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्यातक को जारी की गई हो।

3. यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, यथा :-

(क) यह कि इस स्क्रिप को उन देशों को उन उत्पादों के किये जाने वाले निर्यात के एवज में जारी किया जाता है जो कि भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया पुस्तिका, खंड 1 के परिशिष्ट 37घ में भारत सरकार द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं।

बशर्ते कि निम्नलिखित वर्ग के निर्यात (विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.17.2 में विनिर्दिष्ट) को फोकस प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत निर्यात निष्पदन की गणना में या अधिकार की संगणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यथा :-

(i) निर्यातान्मुखी इकाईयां या इलेक्ट्रॉनिक हॉर्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क या बायोटेक्नोलॉजी पार्क जिनको कि प्रत्यक्ष कर का लाभ मिल रहा है;

(ii) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अंतर्गत आने वाले आयातित माल का निर्यात;

(iii) ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से होने वाला निर्यात, जिसका अर्थ यह है कि निर्यात का प्रारम्भ तो तीसरे देश से हुआ हो लेकिन इसकी ट्रांसशिपिंग भारत से होते हुए की जा रही हो;

(iv) मानक निर्यात;

1597 GI/13-4

(v) विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा किए जाने वाला निर्यात, या विशेष आर्थिक जोन उत्पाद जिनका निर्यात घरेलू टैरिफ क्षेत्रों के माध्यम से किया गया हो;

(vi) ऐसे मद जो कि आईटीसी (एचएस) कि निर्यात नीति की अनुसूची-2 के अंतर्गत निर्यात के लिए प्रतिसिद्ध या निषिद्ध हैं;

(ख) यह कि वह स्क्रिप पंजीयन बंदरगाह पर सीमा शुल्क प्राधिकारी में (तत्पश्चात उपर्युक्त सीमा शुल्क का अधिकारी के रूप में संदर्भित) के पास पंजीकृत होगी;

(ग) यह कि स्क्रिपधारक, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई हैं अथवा प्रदान किये जाने की सहमति की गई है, कर योग्य क्षेत्र में स्थित होगा;

(घ) यह कि स्क्रिपधारक जो कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे मूल रूप में स्क्रिप जारी की गई थी अथवा कोई हस्तांतरित धारक हो सकता है, वह उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को एक पत्र के साथ तथा इनवाइस अथवा चालान अथवा बिल, जैसा भी मामला हो, न्यायनिर्णयन केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी (तत्पश्चात उपर्युक्त प्राधिकारी के रूप में संदर्भित) सेवा कर नियमावली, 1994 के नियम 4 (क) के अंतर्गत सेवा प्रदाता द्वारा संबंधित स्क्रिप को प्रस्तुत करते हुए, उसके विवरण तथा ब्याज, प्रदान की गई अथवा प्रदान किये जाने वाली सहमति वाली कर योग्य सेवा का मूल्य तथा उस पर लगने वाले सेवा कर को इंगित करेगा;

(ङ.) यह कि उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी अधिसूचना सं. 95/2009-सीमा शुल्क, दिनांक 11 सितम्बर, 2009, अधिसूचना सं. 32/2012-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 जुलाई, 2012 के अंतर्गत पहले ही दिये गये डेबिट को तथा इस छूट को मद्देनजर रखते हुए रखेगा, इस प्रकार दी गई छूट को अथवा स्क्रिप के रिवर्स पर लगने वाले सेवा कर का डेबिट करेगा तथा उससे संबंधित अपेक्षित विवरण का भी उल्लेख करेगा और अपने ही रिकार्ड को अद्यतन करेगा तथा उपर्युक्त अधिकारी को कार्यवाहियों के बारे में लिखित सलाह देगा;

(च) यह कि उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा स्क्रिप में लगने वाले सेवा कर डेबिट करने की तारीख को सेवा कर के भुगतान की तारीख के रूप में माना जायेगा;

(छ) यह कि यदि लगने वाला सेवा कर कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के शर्तों के अनुसार निर्धारित किये गये कराधान बिंदु डेबिट किये जाने की तारीख से पहले हो अथवा कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 4 की शर्तों के अनुसार निर्धारित की गई कर की दर, इनवाइस, बिल अथवा चालान, जैसा भी मामला हो, में उल्लिखित सेवा कर दर से यदि अधिक हो, तो स्क्रिप धारा ऐसा ब्याज अथवा ब्याज सहित ऐसा सेवा कर जो कम दिया गया है, जैसा भी मामला हो, भुगतान करेगा;

(ज) यह कि स्क्रिप धारा उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा डेबिट की गई स्क्रिप को संबंधित अधिकारी को, संबंधित अधिकारी को इस वचनबद्धता के साथ प्रस्तुत करेगा कि यदि स्क्रिप में सेवा कर डेबिट में कोई कमी रहती है तो, वह लागू ब्याज सहित ऐसा सेवा कर का भुगतान करेगा ;

(झ) यह कि संबंधित लिखित सलाह तथा वचनबद्धता के आधार पर, संबंधित अधिकारी स्क्रिप के रिवर्स पर लगने वाले सेवा कर के विवरण को सत्यापित तथा वैध करेगा, जोकि उपर्युक्त सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा डेबिट किये गये थे तथा ऐसा सेवा कर तथा ब्याज, यदि कोई हो के भुगतान का रिकार्ड रखेगा।

(ज) यह कि सेवा प्रदाता उपर्युक्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा डेबिट की गई तथा संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित की गई और स्क्रीप धारक द्वारा अनुप्रमाणित की गई स्क्रीप की एक प्रतिलिपि इस अधिसूचना के अंतर्गत कर योग्य सेवाओं के उपबंधों के समर्थन में अपने पास रखेगा; तथा

(ट) यह कि संबंधित स्क्रीप धारा, जिसे कर योग्य सेवाएं प्रदान की गई थी अथवा प्रदान किये जाने की सहमति दी गई थी को स्क्रीप में डेबिट की गई सेवा कर के समक्ष उपर्युक्त अधिनियम की धारा 66ख के अंतर्गत सेवा कर के सेनवेट क्रेडिट अथवा प्रति अदायगी का लाभ प्राप्त करने की हकदारी होगी तथा उसे संबंधित अधिकारी द्वारा वैध किया जायेगा।

4. इस अधिसूचना के अंतर्गत केन्द्र सरकार को दिए कोई भी राशि उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत अपनाई गई नियमावली के प्रावधानों के अंतर्गत वसूली योग्य होगी।

**स्पष्टीकरण -** इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "विदेश व्यापार नीति" से अभिप्राय विदेश व्यापार नीति, 2009-14 से है, जिसको कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 01 (आरई 2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

(ख) "प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-1" से अभिप्राय प्रक्रिया पुस्तिका, खंड-1, 2009-14 से है, जिसको कि भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा लोक सूचना सं. 01(आरई 2012)/2009-2014, दिनांक 5 जून, 2012, समय-समय पर यथा संशोधित, के माध्यम से प्रकाशित किया गया है।

(ग) "कराधान के बिंदु" का अर्थ वही है जो कि कराधान बिंदु नियमावली, 2011 के नियम 2 के उपवाक्य (ड.) के अंतर्गत इसके लिए दिया गया है।

(घ) "क्षेत्रीय प्राधिकारी" से अभिप्राय ऐसे प्राधिकारी से है, जो कि विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) के अंतर्गत इयूटी क्रेडिट स्क्रिप प्रदान करने के लिए सक्षम है।

(ड.) "स्क्रिप" से अभिप्राय ऐसे विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना (स्पेशल एग्रीकल्चर एंड विलेज इंडस्ट्री स्कीम) इयूटी क्रेडिट स्क्रिप से है जो कि विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 3.13.2 के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किसी निर्यातकर्ता को जारी की गई हो।

[फा. सं. 354/55/2013-टीआरयू]

राज कुमार दिग्बिजय, अवर सचिव

1597 GI/13-5

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th April, 2013

**No. 8/2013-Service Tax**

**G.S.R. 256(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the taxable services provided or agreed to be provided against a scrip by a person located in the taxable territory, from the whole of the service tax leviable thereon under section 66B of the said Act.

2. Application. — This notification shall be applicable to the Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (Special Agriculture and Village Industry Scheme) duty credit scrip issued to an exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.13.2 of the Foreign Trade Policy.

3. The exemption shall be subject to the following conditions, namely:-

(a) that the scrip is issued against exports of the products listed in Appendix 37A of the Handbook of Procedures, Volume I:

*Provided* that the following categories of exports (specified in paragraph 3.17.2 of the Foreign Trade Policy) shall not be counted for calculation of export performance or for computation of entitlement under the Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana, namely:-

- (i) the Export Oriented Units or Electronic Hardware Technology Parks or Biotechnology Parks which are availing direct tax benefits or exemption;
- (ii) the export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy;
- (iii) the exports through transshipment, meaning thereby that exports originating in third country but transhipped through India;
- (iv) deemed exports;
- (v) the exports made by Special Economic Zone units or Special Economic Zone products exported through Domestic Tariff Area units;



- (vi) the items, which are restricted or prohibited for export under Schedule-2 of Export Policy in ITC (HS);
- (b) that the scrip is registered with the Customs Authority at the port of registration (hereinafter referred to as the said Customs Authority);
- (c) that the holder of the scrip, to whom taxable services are provided or agreed to be provided shall be located in the taxable territory;
- (d) that the holder of the scrip who may either be the person to whom the scrip was originally issued or a transferee-holder, presents the scrip to the said Customs Authority along with a letter and an invoice or challan or bill, as the case may be, issued under rule 4A of the Service Tax Rules, 1994 by the service provider indicating details of his jurisdictional Central Excise Officer (hereinafter referred to as the said Officer) and the description, value of the taxable service provided or agreed to be provided and service tax leviable thereon;
- (e) that the said Customs Authority, taking into account the debits already made under notification number 95/2009-Customs, dated the 11th September, 2009, notification No.32/2012-Central Excise, dated the 9th July, 2012 and this exemption, shall debit the service tax leviable, but for this exemption in or on the reverse of the scrip and also mention the necessary details thereon, updates its own records and sends written advice of these actions to the said Officer;
- (f) that the date of debit of service tax leviable, in the scrip, by the said Customs Authority shall be taken as the date of payment of service tax;
- (g) that in case the service tax leviable as per the point of taxation determined in terms of the Point of Taxation Rules, 2011 is prior to date of debit or that the rate of tax determined in terms of rule 4 of the Point of Taxation of Rules, 2011, is in excess of the rate of service tax mentioned in the invoice, bill or challan, as the case may be, the holder of the scrip shall pay such interest or short-paid service tax along with interest, as the case may be;
- (h) that the holder of the scrip presents the scrip debited by the said Customs Authority within thirty days to the said Officer, along with an undertaking addressed to the said Officer, that in case of any service tax short debited in the scrip, shall pay such service tax along with applicable interest;
- (i) that based on the said written advice and undertaking, the said Officer shall verify and validate, on the reverse of the scrip, the details of the service tax leviable, which were debited by the said Customs Authority, and keep a record of payment of such service tax and interest, if any;
- (j) that the service provider retains a copy of the scrip, debited by the said Customs Authority and verified by the said Officer and duly attested by the holder of the scrip, in support of the provision of taxable services under this notification; and

(k) that the said holder of the scrip, to whom the taxable services were provided or agreed to be provided shall be entitled to avail the drawback or CENVAT credit of the service tax leviable under section 66B of the said Act, against the service tax debited in the scrip and validated by the said Officer.

4. Any amount due to the Central Government under this notification shall be recoverable under the provisions of the said Act and the rules made there under.

**Explanation—**For the purposes of this notification, -

(A) "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy, 2009-14, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* notification No.01 (RE 2012)/2009-2014, dated the 5<sup>th</sup> June, 2012, as amended from time to time.

(B) "Handbook of Procedures Volume 1" means the Handbook of Procedures Volume 1, 2009-14, published by the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, *vide* Public Notice No.01 (RE 2012)/2009-2014, dated the 5<sup>th</sup> June, 2012, as amended from time to time.

(C) "Point of taxation" shall have the same meaning assigned to it in clause (e) of rule 2 of the Point of Taxation Rules, 2011.

(D) "Regional Authority" means the authority competent to grant a duty credit scrip under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992).

(E) "Scrip" means Vishesh Krishi and Gram Udyog Yojana (Special Agriculture and Village Industry Scheme) duty credit scrip issued to an exporter by the Regional Authority in accordance with paragraph 3.13.2 of the Foreign Trade Policy.

[F. No. 354/55/2013-TRU]

RAJ KUMAR DIGVIJAY, Under Secy.